

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून

दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-494/नि.अ.क./मु.अ.प्रो.यो./2015-15, दिनांक 04 अगस्त, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक संचालन योजना नियमावली-2015 में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में निर्गत दिशा-निर्देशानुसार "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन" योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 10.00 लाख में से रु0 05.00 लाख (रु0 पाँच लाख मात्र) की धनराशि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. राज्य में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत संचालित किये जाने के सम्बन्ध में संगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-329/XVII-3/15-10(बजट)/2012, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा जारी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना योजना नियमावली-2015 का अनुपालन सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र व्यय विचलन से कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन एवं निदेशालय को ससमय उपलब्ध करायी जाय।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 (लेखानियम आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किशतों में किया जाय।



7. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 आयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द लिखा जाय, अन्यथा महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
8. बी.एम.-4 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 2250-00-800- अन्य व्यय 17-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-180(P)XXVII(3)15-16 दिनांक 10 सितम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
12. यह आवंटन अनुदान संख्या-15 के अलोटमेंट आई डी संख्या-S1509150088 दिनांक 10 सितम्बर, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- / 222 / XVII-3/2015-07(49)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास नि.लि.
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

  
(बी०एस० बोरा)  
उप सचिव।